खण्ड-6, अंक-1, वर्ष-2018, मु0पृ0 119-122, D.O.I. : 10.22445/avsp.v6i1.13911 वैज्ञानिक/ज्ञानवर्धक आलेख

क्षेत्रीय असमानता का आधारः शुद्ध विदेशी निवेश

गुंजन पाण्डेय
एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग
बी0एस0एन0वी0 पी0जी0 कॉलेज, लखनऊ–226001, उ0प्र0, भारत
shagunplus1@yahoo.com

प्राप्त तिथि–19.09.2018, स्वीकृत तिथि–28.10.2018

सार–भारत में क्षेत्रीय असमानता नीति निर्माणकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। निजी निवेश, घरेलू तथा विदेशी दो रूपों में देखा जा सकता है। भूमण्डलीयकरण तथा निजीकरण के पश्चात् यह प्रक्रिया और अधिक चुनौतीपूर्ण इसलिए हो गयी है क्योंकि निजी निवेश विकसित समृद्ध राज्यों की तरफ प्रवाहित तथा आकर्षित हो जाता है, जहाँ प्रशिक्षित श्रम शक्ति तथा उपयुक्त कार्य संस्कृति जिसमें समुचित आधारभूत ढाँचा जैसे बिजली, पानी, यातायात इत्यादि की व्यवस्था और उचित कानून व्यवस्था पायी जाती है। जिसके कारण निम्न आय वाले राज्य पिछड़े होते जा रहे हैं और उच्च आय प्रदेश तथा निम्न आय प्रदेशों के मध्य असमानता की खाई बढ़ती चली जा रही है। निजी निवेश की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करने के लिए इस लेख में 14 प्रदेशों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है तथा उत्तर प्रदेश की स्थिति का विशेष रूप से अध्ययन किया गया है।

बीज शब्द– वैश्वीकरण, निजी निवेश, क्षेत्रीय असमानता, आधारभूत संरचना।

Base of regional disparities: pure foreign investment

Gunjan Pandey
Associate Professor, Department of Economics
B.S.N.V. Post Graduate College, Lucknow-226001, U.P., India
shagunplus1@yahoo.com

Abstract- Persistent disparities in regional economic conditions in India continue to offer challenges to policy makers. In the era of globalization and privatization the process of regional growth has become much more complex owing to the expanding role of private investment, be it domestic or foreign. Their flows to the states are highly mobile towards the states with skilled labor force with a good 'work culture', good socio-economic infrastructure and good governance. Private investments have emerged as one of the major source among the various sources of resource transfers which have further led to widening of regional disparities. This article depicts the inter-state study of 14 states and the flow of foreign investment in bringing about disparities.

Key words- Globalization, private investment, regional disparities, infrastructure.

1. **परिचय**– 12वीं पंचवर्षीय योजना का आरम्भ वर्ष 2012 में पूरे देश के साथ उत्तर प्रदेश में भी हुआ। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तेज गति के साथ आर्थिक वृद्धि और साथ ही समावेषी तथा पोषणीय विकास था। इसके अन्य उप उद्देश्यों के अन्तर्गत 10% आर्थिक वृद्धि दर को वर्ष 2017 में प्राप्त करना, अन्तर–प्रदेशीय तथा अन्तः प्रदेशीय विषमताओं में कमी लाना, सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करना तथा निजी निवेश को आकृष्ट करने के लिए समुचित माहौल सृजित करना सम्मिलित थे। भारत में क्षेत्रीय असमानता नीति निर्माणकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्षेत्रीय वृद्धि की प्रक्रिया में निजी निवेश के कारण जटिलता और बढ़ती जा रही है। निजी निवेश, घरेलू तथा विदेशी दो रूपों में देखा जा सकता है। भूमण्डलीयकरण की यह प्रक्रिया और अधिक चुनौतीपूर्ण इसलिए हो गयी है क्योंकि निजी निवेश विकसित समृद्ध राज्यों की तरफ प्रवाहित तथा आकर्षित हो जाता है। जिसके कारण निम्न आय वाले राज्य पिछड़े होते जा रहे हैं और उच्च आय प्रदेश तथा निम्न आय प्रदेशों के मध्य असमानता की खाई बढ़ती चली जा रही है। निजी निवेश की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करने के लिए इस लेख में 14 प्रदेशों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है तथा उत्तर प्रदेश की स्थिति का विशेष रूप से अध्ययन किया गया है। उदारीकरण के पश्चात वित्तीय समझौतों के भाग में बड़ी बढ़ोत्तरी देखी गयी है, शुद्ध विदेशी निवेश को आई0ई0एमस् के माध्यम से दर्शाया गया है। शुद्ध विदेशी निवेश किसी भी

क्षेत्र की उत्पादकता तथा आय के स्तरों को प्रभावित करता है और उस प्रदेश की आर्थिक प्रगति पर भी असर डालता है।

2. **प्रदेशवार विदेशी निवेश प्रवाह का अध्ययन–तालिका–1** में अन्तरराज्यीय विदेशी निवेश(आई0ई0एमस्) लक्ष्यित तथा कार्यान्वित के प्रदेशवार आकड़ों से यह पता चलता है कि उच्च आय वर्ग वाले औद्योगिक राज्यों में आई0ई0एमस् के दाखिल तथा कार्यान्वित का प्रतिशत गुजरात तथा महाराष्ट्र में अधिक पाया गया, जैसे 2015 में गुजरात में 20.77 प्रतिशत तथा महाराष्ट्र में 10.71 प्रतिशत पाया गया, परन्तु उत्तर प्रदेश में 3.66 प्रतिशत जो की बहुत कम है। साथ ही आई0ई0एमस् लक्ष्यित से कार्यान्वित का प्रतिशत और कम है। जो कि गुजरात में 7 प्रतिशत तथा महाराष्ट्र में 24 प्रतिशत पाया गया, परन्तु उत्तर प्रदेश में 2.30 प्रतिशत, जो की बहुत कम है। यह चिन्तन का विषय है।

तालिका–1: प्रदेशवार आई0ई0एम्स लक्ष्यित तथा कार्यान्वित

प्रदेश	आई0ई0एमस् लक्ष्यित		आई0ई0एमस् कार्यान्वित	
	कुल का प्रतिशत	कुल का प्रतिशत	कुल का प्रतिशत	कुल का प्रतिशत
	2014	2015	2014	2015
उच्च आय प्रदेश				
गुजरात	9.79	20.77	52.01	7.68
हरयाणा	0.65	0.91	1.24	1.16
महाराष्ट्र	9.98	10.71	7.65	24.18
पंजाब	0.90	0.65	0.21	0.44
मध्यम आय प्रदेश				
आन्ध्रप्रदेश	5.32	6.90	3.56	5.83
कर्नाटक	5.41	10.26	3.00	17.67
केरल	0.81	1.66	0.05	0.11
तमिलनाडु	3.61	6.37	3.17	0.64
प0 बंगाल	0.69	5.73	4.76	1.26
निम्न आय प्रदेश				
बिहार	0.36	0.41	0.53	0.78
मध्य प्रदेश	2.99	4.22	3.33	22.16
उड़ीसा	6.98	7.98	9.55	0.69
राजस्थान	1.81	2.14	1.96	5.02
उत्तरप्रदेश	3.05	3.66	1.11	2.30
कुल	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

एस0 आई0 ए0 न्यूजलेटर, 2016, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार

तालिका–2 में प्रदेशवार आई0ई0एमस् लक्ष्यित तथा उनका वास्तविक कार्यान्वयन प्रतिशत में दिखाया गया है। आंकड़ों के आधार पर एक बार फिर आर्थिक क्षेत्रीय विषमता सामने देखी जा सकती हैं कि प्रभावी रूप से कार्यान्वयन आई0ई0एमस् का नहीं किया जा रहा है। 2014 में गुजरात में 103.43 प्रतिशत तथा 2015 महाराष्ट्र में 57.27 प्रतिशत पाया गया, परन्तु उत्तर प्रदेश में 7.06 प्रतिशत तथा 15.92 प्रतिशत, जो की बहुत कम है।

अतः यह बात निकल कर आती है कि निम्न आय वाले प्रदेशों में प्रायः निजी घरेलू तथा विदेशी निवेश किये नहीं जा रहे हैं क्योंकि यहाँ निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उचित वातावरण नहीं पाया जाता है। जैसे उचित कानून और व्यवस्था, आर्थिक सुधारों के प्रति अनुकूल वातावरण उद्योग के आरम्भ करने के सरल नियम, आधारभूत ढाँचा जैसे बिजली, पानी, यातायात इत्यादि की समुचित व्यवस्था। इस सब को विकसित करने का उत्तरदायित्व सार्वजनिक क्षेत्र अथवा सरकार का होता है तथा उचित वातावरण न पाये जाने की स्थिति में निवेश निम्न आय प्रदेशों से हस्तांतरित होकर उच्च आय प्रदेशों में पहुँच जाता है।

तालिका–2: अन्तर राज्यीय लक्ष्यित आई0ई0एम्स तथा कार्यान्वित

प्रदेश	प्रस्तावित की अपेक्षा वास्तविक	प्रस्तावित की अपेक्षा वास्तविक
	2014	2015
उच्च आय प्रदेश		
गुजरात	103.43	9.39
हरयाणा	37.08	32.28

महाराष्ट्र	14.92	57.27
पंजाब	4.47	17.12
मध्यम आय प्रदेश		
आन्ध्रप्रदेश	13.04	21.43
कर्नाटक	10.80	43.69
केरल	1.13	1.61
तमिलनाडु	17.13	2.56
प0 बंगाल	135.08	5.58
निम्न आय प्रदेश		
बिहार	28.99	48.92
मध्य प्रदेश	21.71	133.20
उड़ीसा	26.65	2.19
राजस्थान	21.06	59.57
उत्तरप्रदेश	7.06	15.92
कुल	**19.48**	**25.37**

एस0 आई0 ए0 न्यूजलेटर, 2016, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार

तालिका–3: शुद्ध विदेशी निवेश का अन्तर–प्रदेशीय प्रवाह(रू करोड़ में)

क्षेत्रीय मुख्यालय	प्रदेश	2014–15	2015–16	पिछले वर्ष की तुलना में %भाग
मुम्बई	महाराष्ट्र	38933	62731	161.13
नयी दिल्ली	दिल्ली	42252	83288	197.12
चेन्नई	तमिलनाडु	23361	29781	127.48
बेन्गुलुरू	कर्नाटक	21255	26791	126.05
अहमदाबाद	गुजरात	9416	14667	155.77
हैदराबाद	आन्ध्रप्रदेश	8326	10315	123.89
कोलकता	प0 बंगाल	1464	6220	424.86
चंडीगढ़	पंजाब, हरयाणा	234	177	75.64
जयपुर	राजस्थान	3237	332	10.26
भोपाल	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़	601	518	86.19
कोच्ची	केरल	1418	589	41.54
कानपुर	उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड़	679	524	77.17
भुवनेश्वर	उड़ीसा	56	36	64.29
पटना	बिहार, झारखण्ड	68	272	400.00

एस0 आई0 ए0 न्यूजलेटर, 2016, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार

तालिका–3 में विभिन्न राज्यों में शुद्ध विदेशी निवेश का प्रवाह 2014–2015 तथा 2015–2016 में दर्शाया गया है। जिसमें यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि 2014–15 की तुलना में 2015–16 में उच्च आय प्रदेशों में विदेशी निवेश बड़ी मात्रा में बढ़ा हुआ पाया गया। यह प्रतिशत रूपमें 100% से भी पिछले वर्ष से अधिक था। जबकि निम्न आय प्रदेशो में यह प्रतिशत काफी कम देखा गया, अर्थात् वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में निम्न आय प्रदेशों में विदेशी निवेश का प्रवाह कम मात्रा में पाया गया। उत्तर प्रदेश में यह कुल निवेश का 77% मात्र ही देखा गया है।

3. **सुझाव–**

1. पिछड़े प्रदेशों को उन तत्वों को विकसित करना चाहिए जो निजी निवेश करने में सहायक हों, जैसे–श्रमिकों को प्रशिक्षित करना, उचित कार्य संस्कृति, विकसित आधारभूत ढाँचा, तथा अच्छा प्रशासन इनमें सम्मिलित है।
2. सुधार की प्रक्रिया अभी तक केन्द्र स्तर पर ही संकुचित है। प्रदेश सरकार को भी वैधानिक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है क्योंकि कई सम्भावनाएँ सुधार में निहित है। ब्राज़ील, चीन तथा रूस में क्षेत्रीय सरकारों ने सुधार प्रक्रिया लाने में अग्रणी भूमिका निभाई है।
3. प्रदेशों को निजी निवेश हतोत्साहित करने वाले नियमों को परिवर्तित करने की आवश्यकता है तथा निवेश अनुकूल वातावरण स्थापित करने पर बल देना चाहिए।

4. सार्वजनिक निजी साझेदारी को प्रोत्सहित करना चाहिए जिससे आधार भूत ढाँचे के पिछड़ेपन को समुचित निवेश के द्वारा विकसित किया जा सके जो अन्ततः निजी घरेलू तथा विदेशी निवेश को आकर्षित कर सके।

4. **निष्कर्ष–** उदारीकरण के पश्चात वित्तीय समझौतों के भाग में बड़ी बढ़ोत्तरी देखी गयी है शुद्ध विदेशी निवेश को आई0ई0एमस् के माध्यम से दर्शाया गया है। 14 प्रदेशों का प्रदेशवार तुलनात्मक विश्लेषण करने पर पता चलता है कि आई0ई0एमस् के लक्ष्यित तथा कार्यान्वित का प्रतिशत उच्च आय वर्ग वाले प्रदेशों में अपेक्षाकृत अधिक पाया गया जैसे गुजरात तथा महाराष्ट्र परन्तु उत्तर प्रदेश में दोनों प्रतिशत बहुत कम पाये गये। साथ ही आई0ई0एमस् लक्ष्यित कार्यान्वित का प्रतिशत निम्न आय प्रदेशों में और कम है, जो कि चिन्तन का विषय है। आंकड़ों के आधार पर एक बार फिर आर्थिक क्षेत्रीय विषमता सामने देखी जा सकती है। प्रभावी रूपसे आई0ई0एमस् का कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है। उच्च आय प्रदेशों में विदेशी निवेश बड़ी मात्रा में बढ़ा हुआ पाया गया, जबकी निम्न आय प्रदेशों में यह प्रतिशत काफी कम देखा गया। यह सिद्ध होता है कि आर्थिक सुधार काल में किसी प्रदेश में आय के स्तर को प्रभावित करने में निजी निवेश को आकृष्ट करने की एक अहम भूमिका रही है। पिछड़े प्रदेश निजी निवेश आकृष्ट करने में असफल हुए हैं क्योंकि इनमें निवेश हेतु वातावरण अनूकुल नहीं पाया जाता है, जिसमें आधारभूत ढाँचे की बुरी दशा सम्मिलित होती है। ये प्रदेश निवेश वातावरण में सुधार लाने में असफल है क्योंकि संसाधनों की कमी के कारण इनका आधारभूत ढाँचा पिछड़ी अवस्था में पाया जाता है। आवश्यकता है किसी नितिगत हस्तक्षेप की जिससे शुद्ध प्रत्यक्ष निवेश का प्रवाह नियंत्रित करके पिछड़े प्रदेशों में उनका विकास करके स्थानान्त्रित किया जाए।

संदर्भ

1. सिंह, अहलूवालिया मोनटेक(2000) स्टेट लेवेल परफोर्मेन्स अंडर इकोनॉमिक रिफार्मस् इन इण्डिया, आई0 जे0 अहलूवालिया तथा आई0एम0डी0 लिट्टिल, इन्डियन इकोनॉमिक रिफार्म एण्ड डेवेलेपमेन्ट एसेज फॉर मनमोहन सिंह।
2. कुरियन एन0 जे0(2000) वाइडिनिंग रीजनल डिस्पेरिटीज इन इण्डिया सम इनडिकेर्टस, इकोनॉमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, फरवरी 12, 2002, पृ0 538।
3. एस0आई0ए0 न्यूजलेटर–2016, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार।
4. डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.इन्डियास्टेट.कॉम
5. सेन्सेसऑफइन्डिया, वर्ष–2011।